



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 256]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 6, 1972/आश्विन 14, 1894

No. 256]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 6, 1972/ASVINA 14, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October 1972

**G.S.R. 430(E).**—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Maintenance Orders Enforcement Act, 1921 (18 of 1921), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Maintenance Orders Enforcement Rules, 1955, namely:—

1. These rules may be called the Maintenance Orders Enforcement (Amendment) Rules, 1972.

2. In the Maintenance Orders Enforcement Rules, 1955, to rule 8, the following proviso shall be added at the end, namely:—

“Provided that, in the State of Maharashtra, in Greater Bombay, the Chief Presidency Magistrate, and elsewhere the District Magistrate, shall, for the purpose of enforcing any maintenance order registered or confirmed by him under the Act, have the powers exercisable by a Presidency Magistrate and a Magistrate of the first class, respectively, under sub-section (3), but excluding the provisos thereto, and sub-section (7), of the said section 488”.

[No. F.10(2)/70-Judl.]

P. G. GOKHALE, Jt. Secy. & Legal Adviser.

( 2011 )

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 1972

सा०का०नि० 430(अ).—भरण-पोषण आदेश प्रवर्तन अधिनियम, 1921 (1921 का 18) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भरण-पोषण आदेश प्रवर्तन नियम, 1955, में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम भरण-पोषण आदेश प्रवर्तन (संशोधन) नियम, 1972 है ।
2. भरण-पोषण आदेश प्रवर्तन नियम, 1955 में, नियम 8 के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु, महाराष्ट्र राज्य में, ग्रेटर बम्बई में, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, और अन्यत्र, जिला मजिस्ट्रेट को, अधिनियम में अधीन उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत या पुष्टि किए गए किसी भरण-पोषण आदेश को प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिए, उक्त धारा 488 की उपधारा (4), किन्तु उसके परन्तुकों को छोड़कर, और उपधारा (7) के अधीन क्रमशः प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों होंगी ।

[सं० एफ० 10(2)/70-जे०]

पी० जी० गोखले,

संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार ।